



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



17 माघ, 1945 (श०)

संख्या - 74 राँची, मंगलवार,

6 फरवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

22 दिसम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-435/2014 का०-7173--श्रीमती नमिता नलिनी मिंज (बाखला), झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-776/03 गृह जिला- राँची), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया, गुमला, सम्प्रति- मृत के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-10903, दिनांक 07.12.2007 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध सरकारी राशि का गबन / दुरुपयोग, सरकारी वाहन का दुरुपयोग, रोकड़-पंजी के संधारण में वित्तीय अनियमितता, मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहने एवं आदेश की अवहेलना एवं पद का दुरुपयोग करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-738, दिनांक 08.02.2008 द्वारा श्रीमती मिंज के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-129, दिनांक 19.07.2013 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसमें आरोपों को प्रमाणित पाया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए

विभागीय संकल्प सं०-2129, दिनांक 28.02.2014 द्वारा इनके विरुद्ध चार वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्रीमती मिंज द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-10977, दिनांक 17.11.2014 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्रीमती मिंज द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में W.P.(S) No. 6697/2014 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा 14.06.2023 को पारित आदेश में विभागीय संकल्प सं०-2129, दिनांक 28.02.2014 द्वारा अधिरोपित चार वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक के दण्ड एवं विभागीय पत्रांक-10977, दिनांक 17.11.2014 द्वारा अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत से संबंधित निर्गत आदेश को रद्द कर दिया गया। उक्त न्यायादेश का Operative Part निम्नवत् है

"Accordingly, on the basis of discussions made hereinabove, this Court is of the view that the impugned order of punishment requires interference and hence order dated 28.02.2014 passed by the disciplinary authority as also appellate order dated 17.11.2014 are hereby quashed and set aside.

In consequence thereof, the respondents-State are hereby directed to calculate the difference of arrears of salary and pensionary/retiral benefits and release same in favour of legal heirs of the deceased-employee within a period of three months from the date of receipt/production of copy of this order."

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2023 को पारित आदेश के आलोक में श्रीमती नमिता नलिनी मिंज (बाखला), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया, गुमला, सम्प्रति-मृत के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-2129, दिनांक 28.02.2014 द्वारा अधिरोपित चार वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक के दण्ड एवं विभागीय पत्रांक-10977, दिनांक 17.11.2014 निर्गत आदेश को रद्द किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती नमिता नलिनी मिंज (बाखला), कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी एवं अन्य संबंधितों को भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
